

85 करोड़ लीटर बायोडीजल खरीदेंगी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां

[संजीव चौधरी | नई दिल्ली]

सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल में मिलाने के लिए बायोडीजल की खरीदारी की शुरुआत कर दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने लोकल मैन्यूफैक्चरर्स से 85 करोड़ लीटर बायोडीजल की खरीदारी के टेंडर जारी किए हैं। टेंडर डॉक्युमेंट के मुताबिक, इस पूरी क्वोटान्टी का करीब 40 फीसदी हिस्सा अकेले IOCL खरीदेगी, जबकि बाकी हिस्से को BPCL और HPCL खरीदेंगी। बायोडीजल को अगस्त से लेकर मार्च 2016 तक देश की अलग-अलग लोकेशनों पर डिलीवर किया जाएगा। टेक्निकल और प्राइस बिडिंग की 19 अगस्त तक ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है।

ऑयल इंडस्ट्री के एक एजिक्यूटिव ने बताया कि इस पहली खरीदारी से रिटेलरों को बायोडीजल की कीमत हासिल करने और अनिवार्य होने पर इसकी ब्लेडिंग के लिए तैयार रहने में मदद मिलेगी। यह बायोडीजल वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट से तैयार किया हुआ हो सकता है। बायोफ्यूल्स पर नेशनल पॉलिसी में 2017

तक बायोडीजल IOC, BPCL और एथेनॉल दोनों और HPCL में 20 फीसदी ब्लेडिंग रेशियो ब्लेडिंग से का प्रस्ताव किया गया था। अब तक खरीदारी के टेंडर सरकार ने केवल 5 जारी किए हैं फीसदी एथेनॉल की ब्लेडिंग को अनिवार्य

बनाया है। एथेनॉल को ज्यादातर शुगर और कॉर्न से पैदा किया जाता है। इसकी ब्लेडिंग पेट्रोल में होती है। बायोडीजल की उपबलब्धत के बारे में अनिश्चितता ने भी इसकी ब्लेडिंग को अनिवार्य बनाने की प्रोसेस को सुस्त बना रखा है।

फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को घटाने की कोशिश में सरकार एथेनॉल और बायोडीजल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। गौरतलब है कि फॉसिल फ्यूल्स सीधे तौर पर वायु प्रदूषण फैलाते हैं। तौन महीने पहले सरकार ने पेट्रोल में ब्लेडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल पर लगने वाली 12.36 फीसदी की एक्साइज इयूटी को खत्म कर दिया था, साथ ही सरकार ने शुगर पर इंपोर्ट इयूटी को पहले के 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया था, ताकि लोकल शुगर इंडस्ट्री को मदद मिल सके। इंडिया अपनी खपत का 80 फीसदी कूड़ इंपोर्ट करता है और 5 फीसदी बायोडीजल और एथेनॉल ब्लेडिंग से इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज में खासी बचत हो सकती है। हेल्थ को हो रहे नुकसान और इसके राष्ट्रीय मसला बनने से इंडिया स्वच्छ फ्यूल पर जोर दे रहा है।

इकाईभिक हाइम्स
३१८।१५